

न्यायालय अति० जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु०नं० 45/2018

तारीख रजू:-19.12.2018

1 सुजान पुत्र कोरया जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोडूपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली :-

अपीलान्त

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली

-रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 28.9.2018 न्यायालय तहसीलदार तहसील सपोटरा
जिला करौली

निर्णय

दिनांक 15.1.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वकील अपीलान्त ने एक अपील अपीलान्त की ओर से नायव तहसीलदार सपोटरा के निर्णय दिनांक 28.9.2018 से नाखुश होकर बताया गया है कि मातहत अदालत ने अपीलान्त को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का नोटिस नहीं दिया गया है बिना सुनवाई के एक तरफा कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का ने रंजीस बस अपीलान्त के विरुद्ध किया गया है किसी प्रकार का मौके पर कब्जा नहीं है। ना ही किसी प्रकार का कोई निर्माण किया है न्यायालय द्वारा बिना विधि विरुद्ध तरिके से बिना माइण्ड एप्लाइ किये ही निर्णय पारित किये गया है। इस निर्णय की जानकारी अपीलान्त को दिनांक 27.11.2018 को प्राप्त हुयी जानकारी से पूर्व अपीलान्त को इस निर्णय का कोई पता नहीं है। अपील अपीलान्त बाद जानकारी अन्दर म्याद श्रीमान की सेवा में पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्त दर्ज पंजीका कर रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

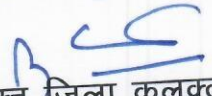
वकील अपीलान्त की बहस सुनी गई दौराने बहस अपने कथन में अपील मीमो को दोरते हुये कहा गया है कि अपीलान्त की तामिल सही नहीं कराई गई है। ना ही अपीलान्त को सुना गया है। अपीलान्त द्वारा किसी प्रकार का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। जो रिपोर्ट की गई है वो गलत है। पटवारी से जिरह नहीं कराई गई है पश्चावर्ती अतिचार के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विधि अनुसार अपीलान्ती को सुना जाना आवश्यक है अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्त की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि पटवारी हल्का भरतून ने एक रिपोर्ट राजकीय भूमि चरागाह खसरा नम्बर 875 रकवा 4 विस्वा पर पक्की दीवार व बाडा बनाकर अतिक्रमण किया गया था जिसमें नायव तहसीलदार सपोटरा द्वारा अतिक्रमी/अपीलान्ती को धारा 91 एल.आर.

अपीलान्ट /अतिक्रमी इस अतिचार को नही हटा रहा है जिसके कारण आम जन को सार्वजनिक भूमि को उपयोग उपभोग मे बाधा उत्तपन्न हो रही है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नही है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है। नायव तहसीलदार सपोटरा का निर्णय दिनांक 28.9.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय दिनांक 15.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली